उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुमाग संख्याः 67/ /VII-1/2013/75-उद्योग/2012 देहरादून : दिनांकः 2.3 उनास् 2013

अधिसूचना

र औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 940/औ०वि०/ 07-जद्योग/2004-05. दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति-निर्देशों एवं शासनादेश संख्या 387/697-स0नि0/पीएस/आईडी/06. दिनांक 20 दिसम्बर, 2008 द्वारा मैगा प्रोजेक्ट्स हेतु अधिसूचित भूमि के विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने सम्बन्धी प्राविधानों तथा उद्योग निदेशालय के संस्तुति सम्बन्धी पत्र संख्या 3170/उ०नि०(पांच)-मैगा प्रोजैक्ट/10-11. दिनांक 17 अक्टूबर, 2011 एवं पत्र संख्या 1718/ उ०नि०(पांच)-मैगा प्रोजैक्ट/ 2012-13, दिनांक 19 जुलाई, 2012 के संदर्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विमाग) की अधिसूचना संख्या 60/2003-सैन्ट्रल एक्साईज, दिनांक 10.08.2003 के कम में जनपद उधमसिंहनगर की तहसील काशीपुर के ग्राम महुवाखेडागंज के खसरा संख्या 1068, 1069 एवं 1075 कुल रकवई 1.89 हैक्टेयर अर्थात् 4.670 एकड़ भूमि में मेगा प्रोजैक्ट की स्थापना हेतु मै० शेख मुल्लन एण्ड सन्स (मेगा प्रोजिक्ट). इण्डस्ट्रियल एरिया, महुवाखेडागंज, काशीपुर, जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में निम्नलिखित प्रतिवन्धों / शर्ती के अधीन विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्त विमाग) की अधिसूचना संख्या 50/2003 सी0ई0, दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure -!! में जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत भूमि का खसरा संख्या 1068, 1069, 1075 Category-B "Proposed Industrial Area/Estate" के रूप में कमाक-8 पर ग्राम महुवाखेड़ागज, तहसील काशीपुर के सम्मुख स्तम्म-4 में अधिसूचित है। इस अधिसूचित मूमि पर स्थापित होने वाले प्रस्तावित नये उद्योग को विशेष पैकेज के अन्तर्गत आयकर छूट तथा केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान सहायता का लाभ अर्हता पूर्ण करने

पर अनुमन्य होगा। जी०आई०डी०सी०आर०-2005 में औद्योगिक इकाई के भवन निर्माण के लिए दिये गये मानकों

विधियों / उपविधियों व उपवन्ध का पूर्णतः पालन करना होगा।

इस विशेष औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्य कर अर्जित की गयी है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमः जी०आई०डी०सी०आर०-2005 के उपबन्धों के अनुरूप आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) से स्वीकृत करायेंगे।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में उद्धितखित शती एवं प्रतिबन्धों

का पर्णतः पालन करना होगा।

विशेष औद्योगिक आस्थान के रख-रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास अन्य नागरिक सुविद्याओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। कम्पनी द्वारा आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सम्बन्ध में स्पष्ट सभी सूचनाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी।

विशेष औद्योगिक आस्थान को विकसित करने के लिए विभिन्न विभागों यथा वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अनि शमन विभाग, चताराखण्ड पॉवर कारपॉरेशन आदि से वांछित

6.

विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित हाँगी, वह प्रवर्तक/ब्रावेदक द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।

 आस्थान के प्रवर्तक द्वारा यह अन्दर्रटिकेंग लिखित में दी जायेगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त 10 प्रतिशत रेजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जावेगा।

क्य की जाने दाली मूनि का उपयोग Manufacture of Cotton Woolen and Silk Carpets other made by hand आदि उत्पादों के विनिर्माण की इकाई के स्थापना हेतु ही किया जावेगा।

8. विशेष क्रीटोनिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर जारी विशा-निर्देशों, यथा प्रदेश की क्रीटोगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईगां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलत है, की स्थापना मही की जावेगी।

उपरोक्त उत्तिकित प्रतिबन्धी/शर्ती का उत्तिपन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिसे बासन उद्यति समझता हो, सदान अधिकारी के अनुमोदन से इस अधिसूचना को निरस्त किया जा सकता है।

्रितिकेश शमी) जापर सुरुप सन्धित ।

पुष्ठांकन संख्याः ६२/ (1)/VII-1/2013/75-उद्योग/2012, तद्दिनांकित। प्रतितिपि निम्नतिष्ठित को सूचनार्य्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित :--

1 निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निजी सिंघर, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।

- 3. संयुक्त सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औ० नीति संवर्धन विभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली।
- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य कर्जा निगम, कर्जा भवन, देहरादून।

5 जिलाधिकारी, उघमसिंहनगर।

प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

है सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्यमसिंहनगर।

10. मैतर्स शेख मुल्लन एण्ड सन्स (नैगा प्रोजक्ट). इण्डस्ट्रीयल एरिया, महुवाखेडागंज, काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर।

11. गार्ड फाईल।

(तैलेशे बगौली) अपर सचिव।